श्री प्रेम चन्द वर्मा : इसी मद्रास पोर्ट पर इसी केस के साथ एक पिग आयरन का केस भी हुआ है। 1476 मैट्रिक टन पिग आयरन जिसकी कीमत विदेशी मुद्रा में 4 लाख 74 हजार रुपये या पांच लाख रुपये के करीब होती है वह कम पाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में आपने इनक्वायरी की है और क्या इस शार्टेज को कम्पनी की तरफ से पूरा करवाया गया है। यह जो पांच लाख रुपये के विदेशी एक्सचेंज, फारेन एक्सचेंज का घोटाला है उसके मुताल्लिक मेरी इत्तिला यह है कि पांच लाख रुपया उसी देश में जहां से पिग आयरन आया, यहां के अफसरों ने वहां पर वह रकम वसूल की है। इसके बारे में क्या पोजीशन है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने मेरे साथी से इसका जिक्र किया है। मुझे इसकी जांच करवानी पड़ेगी।

FREE TRADE ZONE AT HALDIA

+

*843. SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a free trade zone at Haldia without awaiting the results of free trade zone recently established at Kandla, keeping in view the fact that unlike Kandla, Haldia has one of the most industrialised hinterland to provide skill and experience as well as raw materials for the manufacture of engineering goods for export; and

(b) if so, at what stage the matter rests at present ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : (a) No, Sr.

(b) The question does not arise.

SHRI S. C. SAMANTA : May I know what factors were taken into consideration when Kandla was declared as a free trade zone and whether at that time there was opposition saying that first Kandla should be connected by railways and, if so, what been done in the matter ?

SHRI DINESH SINGH : This matter has been gone into fully in this House on several occasions. Various considerations were before the government when they had to decide this matter. It would be a long story for me to give it in the question hour just now. If you so wish, I shall send to the hon. Member a small note on this.

SHRI S. C. SAMANTA : Is it not a fact that the chamber of commerce and other business interests have demanded a free trade zone at Haldia because of the heavy exports from Haldia ?

SHRI DINESH SINGH : Yes, Sir. We had representations from certain bodies in this connection and they were all considered.

SHRI T. M. SHETH : May I know whether any legislation for a free trade zone at Kandla is proposed to be undertaken ?

SHRI DINESH SINGH : Not that I am aware of.

श्री महाराज सिंह भारती : विदेशी मुद्रा का संकट हमारे सामने है। दुनिया का जो इस तरह के खुले बंदरगाह बनाने का तजुर्बा है जिसके द्वारा टैक्स नहीं लगते है और सस्ती कीमत पर माल लोगों को, विदेशी लोगों को दिया जाता है और विदेशी लोग बहुत खरीद लेते हैं, वह भी आपके सामने है। मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों तक विचार करने के बाद भी क्या उसकी कोई मुकम्मिल रूपरेखा सरकार आज तक नहीं बना पाई है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, इनकी पूरी रूपरेखा बन गई है और यहां काम भी शुरू हो गया है।

PRODUCTION OF MILK FOOD AND PROTEIN ISOLATES

*844. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to encourage the production of milk food and protein isolates to enrich the diet;

(b) whether it is also a fact that some foreign concerns are interested in manufacturing protein isolates from oil cakes; and

(c) if so, the steps which Government propose to take to remove the shortage of such type of food ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) All possible assistance is being rendered to develop milk foods and other protein rich foods in the country.

श्री कंवर लाल गुप्त : हमारे देश में करीब दस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता है और करीब तीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंडर-नरिशड हैं। कभी इस बात का आपने सर्वे किया है कि हमारे यहां जो भोजन है उसमें पौष्टिक पदार्थों की और रिच डायट की जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कितनी कमी है और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है कि सब लोगों को रिच डायट या जितनी हैल्थ को मेंटेन करने के लिए डायट की आवश्यकता है उतनी मिल सके ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या कदम उठा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हमारा जो सर्वे है उससे मालूम होता है कि काफी डैफिशेंसी है न्यूट्रिशस डायट की और प्रोटींज की खास कर। बैलेंस्ड डायट के लिए लीफी वैजीटेबल्ज, एग्ज, मीट और प्रोटीन डायट की बहुत जरूरत है जोकि ग़रीब लोग महंगी होने की वजह से नहीं खा सकते हैं।

इसके अलावा कुछ लोगों की फूड हैबिट्स ऐसी है कि वे मीट वग़ैरह नहीं खाते हैं। उनको भी प्रोटीन डाइट की डेफ़िशेंसी होती है।

श्री राजसेवक यादव : इसमें आदत का सवाल है या दाम का सवाल है, क्योंकि मांस तो बहुत महंगा है। क्या बकवास बोलते हैं।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : दोनों वजहें हैं। इस लिए इस बात पर ग़ौर किया जा रहा है कि सस्ती बेलेंस्ड डाइट के लिए प्रोटीन मुहैया कर के दिया जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कौन-से स्पेसिफ़िक स्टेप लिये हैं। मंत्री महोदय बतायें कि क्या सरकार ने इस बारे में अभी तक कुछ किया है या नहीं और आगे वह क्या करने वाली है। उनको वेग नहीं होना चाहिए।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : यह काम हाथ में लिया जा रहा है कि दूध वग़ैरह ज्यादा बनाया जाये और लोगों को सस्ते दाम पर दिया जाये और प्रोटीन के कारखाने खड़े करके सस्ते दामों पर प्रोटीन को दूध में मिला कर दिया जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : बच्चों की खुराक की भी बहुत कमी है और जो हमारे देश में बनती है, वह बहुत महंगी है। ग़रीब आदमी अपने बच्चों के लिए उसको एफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में बेबी फूड कितना बनाया जा रहा है और कितनी उसकी जरूरत है, फ़ारेन इनवेस्टर्ज के साथ कोलैबोरेशन में कहां तक प्रोग्रेस हुई है, उन्होंने क्या कहा है और सरकार ने क्या कहा है।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मेसर्ज प्रोटीन एंड केमिकल्ज, बम्बई, 4800 टन आइसोलेट्स ग्राउंडनट से बनाने के लिए भावनगर, गुजरात स्टेट, में एक अमरीकन कम्पनी के कोलैबोरेशन के साथ एक प्लांट खड़ा करना चाहते हैं। यह मामला ज़ेरे-ग़ौर है। मेसर्ज टाटा आयल मिल्ज ने भी 3000 टन ग्राउंडनट आटा और 1500 टन प्रोटीन आइसोलेट्स के मैनुफ़ैक्चर के लिए दरख्वास्त दे रखी है। मेसर्ज फूड एंड एलाइड प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड बम्बई ने 6000 टन प्रोटीन फूड तैयार कर रहे हैं। मेसर्ज सोयापेक्स सोयाबीन्ज से हाई प्रोटीन फूड

बनाना चाहते हैं। वह एक अमरीकन कम्पनी के साथ मिल कर काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने उस प्रोपोज़ल को एपरूव कर लिया है। मैसर्ज जीवनलाल एंड सन्ज़ एड रत्नम्, बम्बई, को भी सोया वेजीटेबल प्राडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया गया हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे इन कम्पनियों और फ़ार्मों वग़ैरह में दिलचस्पी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितना बेबी फूड बनता है और कितने की ज़रूरत है और उसको सस्ता करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : कितना बेबी फूड बनता है, यह हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है। हम तो इसके लिए लाइसेंस देते हैं।

श्री रामसेवक यादव : अभी मंत्री महोदय ने मांस और हरी सब्ज़ियों की बात चलाई, जिनमें प्रोटीन होता है। हम अपने लोगों को अनाज तो दे नहीं पा रहे हैं और हरी सब्ज़ियां या मांस तो अनाज से भी ज्यादा महंगी है। जहां तक बेबी फूड का सम्बन्ध है, हमारे यहां जो बेबी फूड तैयार होता है, वह किस आमदनी के ग्रुप के लोगों में बंटता है? अगर वह साधारण लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो क्या उसको उन तक पहुंचाने के लिए कोई सबसिडी या सहायता करने का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है, वर्ना बेबी फूड केवल सम्पन्न लोगों को ही मिलेगा, साधारण लोगों को नहीं?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : जहां तक हम से हो सकता है, हम दूध बढ़ाने और प्रोटीन मिला कर दूध का इन्तज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां स्कूलों के ज़रिये से बच्चों को यह दूध देने की कोशिश कर रही है।

श्री रामसेवक यादव : मंत्री महोदय ने सबसिडी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री राम गोपाल शालवाले : देश में करोड़ों बच्चों को दूध नहीं मिलता है और इस देश में लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जो मांसाहारी नहीं है, जो मांस या अंडा नहीं खाती है। मंत्री महोदय ने अभी मांस और अंडे की चर्चा की है, लेकिन इस देश में बार-बार गो-हत्या को बन्द करने के लिए आन्दोलन किये जाते हैं, ताकि दूध की मात्रा बढ़े। मैं यह जानना चाहता हूं कि गो-हत्या को बन्द करने और इस प्रकार दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन से पग उठाए हैं।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : इस वक्त 12 मिलियन लिटर्ज़ आफ़ मिल्क हर साल हमारे देश में हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 5 मिलियन लिटर्ज़ और बढ़ाया जाये।

श्री राम गोपाल शालवाले : गो-हत्या बन्द करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

SHRI PASHABHAI PATEL : Sir, there is a cultural side also to this. They are making baby foods and so on containing non-vegetarian food. But there is a vast population in India which is vegetarian. Is any consideration being given to this aspect? Most of the baby foods may contain non-vegetarian food about which we do not know and our children might be taking it without knowing.

SHRI F. A. AHMED : I could not follow the question.

SHRI PASHABHAI PATEL : The position is this that when Government is starting preparation of baby foods and other protein rich foods, do they keep an eye on non-vegetarian and vegetarian foods—I know some of the milk products are mixed with fish proteins, is it so or is it not?—because this country is essentially a cultural country where a vast population is vegetarian and without knowing that they may become non-vegetarian. Is Government doing anything about that because they are always talking of fish.

MR. SPEAKER : You must keep the baby food purely vegetarian.

SHRI F. A. AHMED : So far as protein manufacture is concerned, it is supposed to be manufactured out of vegetarian things like soya bean and many other oil seeds.

MR. SPEAKER : The Minister assures that it is all vegetarian.

SHRI AMRIT NAHATA : Does the hon. Minister know that there is a part in our country known as the Thar desert in the north-western Rajasthan where milk is cheaper than water, but since the area is cut off from the rest of the country, would the Minister consider setting up a modern dairy there to produce baby foods and milk products so that they can be supplied to the rest of the country ?

SHRI F. A. AHMED : I will forward the suggestion of the hon. Member to the Food Minister.

श्री राम चरण : हमारा शहर खुर्जा सारे हिन्दुस्तान में हमेशा घी के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन जब से केन्द्रीय सरकार ने हमारे क्षेत्र में ग्लैक्सो लैबारेटरीज नाम की एक प्राईवेट लिमिटिड कम्पनी को बेबी फूड और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने का प्लांट लगाने दिया है, तब से हम अनाथ जैसे हो गये हैं और हमें शुद्ध दूध तथा घी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का सारा दूध उस कम्पनी के यहां चला जाता है। क्या सरकार ऐसी प्राईवेट कम्पनीज़ को हमारे क्षेत्र में प्लांट बनाने और दूध इकट्ठा करने से रोकेगी, जिससे वहां के लोगों को शुद्ध दूध और घी उपलब्ध हो सके ?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : एक तरफ़ तो यह मांग की जा रही है कि इस किस्म के फूड की प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा किया जाये और दूसरी तरफ़ कहा जा रहा है कि जो इस किस्म की दूध की प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, उनको रोक दिया जाये।

COMPANIES' CONTRIBUTIONS TO POLITICAL PARTIES

+

*845. SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the different Ministries of the Government of India who were examining the proposal to stop completely the companies' contributions to political parties have finalised their proposals;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मंत्री महोदय जानते हैं कि समवायों के द्वारा राजनीतिक दलों को, और ख़ासतौर से शासक दल को, अंशदान दिये जाने के कारण शासन की आर्थिक नीतियां प्रभावित होती हैं और उसके कारण हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में एकाधिकार के निहित स्वार्थ तथा आर्थिक विषमतायें आदि कई समस्यायें पैदा होती है। क्या सरकार तत्काल कोई इस प्रकार की नीति अपनाने या कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिससे कोटा और परमिट आदि के सम्बन्ध में जो अनियमिततायें और पक्षपात चल रही है, उनको तत्काल रोका जा सके ?

SHRI RAGHUNATH REDDI : Sir, this question arose on the floor of this House as well as the other House several times. In fact hon. Shri Madhu Limaye had moved a Bill and during the course of discussion Government had given him an undertaking that after examining the various aspects of this question a Bill will be in introduced in order to achieve the purpose of banning contributions to political parties by companies. The only thing which has delayed the introduction of the Bill during the current session is this. It is not merely a question of the companies registered under the Companies Act which will have to be taken into account but also of private firms, partnerships and trusts which are not covered by the company law. Therefore, to achieve the very purpose which the hon. Member has mentioned, namely to prevent the corruption of public life by the inroads made by the private moneys, the form in which the legislation will have to be brought